







# सम्पादकीय

## न्याय का धज ऊंचा रहे

भारत के लोकतन्त्र की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि इसके चार पायों में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका ने कभी भी न्याय का पलड़ा झुकने नहीं दिया है। बेशक इमरजेंसी के 18 महीनों के समय को हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं। मगर कार्यपालिका या विधायिका यहां तक कि चुनाव आयोग भी जब अपनी जिम्मेदारी से गमिल हुआ है तो न्यायपालिका ने दिशा दिखाने का काम किया है और लोकतन्त्र के ध्वज को ऊंचा फहराया है। चंडीगढ़ नगर निगम के महापैर के चुनाव में जो भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई मतदान अधिकारी अनिल मसीह द्वारा हुई उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने न केवल सुधारा बल्कि मसीह पर मुकदमा चलाने की तजवीज पेश करके भी एक मिसाल कायम की जिससे आगे कभी भी कोई मतदान अधिकारी ऐसी बेशर्मी और बेहयायी करके लोकतन्त्र का मजाक न बना सके। यदि और साफशब्दों में कहा जाये तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल मसीह पर लानत भेजने का काम किया है क्योंकि उसका काम भारत के लोकतन्त्र को पूरी तुनिया की निगाह में नीचे गिराने वाला था। जिस तरह उसने आप व कांग्रेस गठबन्धन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े आठ वोटों को अवैध घोषित किया था वह कार्रवाई नादिरशाही की याद दिलाती है। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में पूरे मामले को लोकतन्त्र की हत्या भी कहा था। मुख्य न्यायाधीश श्री डॉ. वार्ड. चन्द्रचूड़ ने अवैध किये गये आठ मतों को पूरी तरह से वैध मानते हुए कुलदीप कुमार को मेयर पद पर निर्वाचित घोषित करके ऐसी नजीर बनाई है जिसका अनुसरण लोकतन्त्र में आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। मगर जिस तरह से आप पार्टी के तीन पार्षदों का पाला बदलवा कर और पहले बेइमानी से घोषित मेयर मनोज सोनकर से इस्तीफ दिलवा कर बाजी को अपने ही हक में रखने की जो राजनैतिक शत्रुंद बिछाई गई थी, उसे न्यायमूर्तियों ने तार-तार करते हुए पुराने पड़े वोटों की ही पुनः गिनती करा कर सिद्ध कर दिया कि न्याय को किसी भी चाल से दबाया नहीं जा सकता है और सच लाख पर्दों से भी बाहर आने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक न्याय भी यही कहता था कि कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उह्नें 16 के मुकाबले 20 वोट मिले थे। इन 20 वोटों में से ही आठ को अवैध घोषित करके अनिल मसीह ने हारे हुए प्रत्याशी मनोज सोनकर को विजयी बनाने का काम किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों को आने ही नहीं दिया जिससे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव दोबारा कराया जाता। यदि ऐसा होता तो 36 सदस्यीय नगर निगम में दल बदल के बाद भाजपा के 19 वोट हो जाते और आप व कांग्रेस गठबन्धन के 17 वोट रह जाते जिससे पुनः मनोज सोनकर जीत जाते। बिद्वान न्यायमूर्तियों ने प्राकृतिक न्याय की रूह से फैसला किया कि पुराने मतों की पुनः गिनती करायी जाये और विधायिका में खरीद-फौखां के भरोसे जो दल-बदल किया जाता है उस पर लानत फैंकी जाये। उह्नोंने पुराने वोटों की ही गिनती करा कर वैध मतों को अवैध करार देने की प्रक्रिया को अलग करते हुए कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया। इससे यही साबित हुआ कि भारत का लोकतन्त्र कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि इसे जो चाहे जिस तरह मोड़ कर अपनी जेब में रख ले। यह कुछ मान्य सिद्धान्तों और परंपराओं पर टिकी हुई शुद्ध प्रणाली है जिसका पालन करना हर राजनैतिक दल का परम कर्तव्य है। लोकतन्त्र के लिए लोकलज्जा इसीलिए जरूरी है जिससे जनता का इस पर हमेसा विश्वास जमा रहे।

## चंडीगढ़ का संदेश

चंडीगढ़ में मेरय पद के चुनाव के दौरान अनुचित तौर-तरीके अपनाए जाने के आरोपों के बाद सामने आए नवीजे के रूप में जो अलोकतांत्रिक स्थिति उपजी थी, उसे शीर्ष अदालत के निर्णय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब सवाल यह है कि जब एक नगर निगम के मेरय के चुनाव में इस स्तर तक धांधली हो सकती है तो बड़े चुनावों को लेकर राजनीतिक दल स्तर तक जा सकते हैं? यहाँ सवाल सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर तो है ही, प्रश्न इस केंद्र शासित प्रदेश के उन आला अधिकारियों पर भी उठते हैं जिनकी जवाबदेही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाये रखने के लिये थी। चंडीगढ़ नगर निगम का सवाल इसीलिये अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तरह यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा नहीं है। इस प्रकरण से सवाल इस केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन में दखल रखने वाले केंद्र के बड़े अधिकारियों पर भी उठते हैं। विपक्षी दल इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल के इस्तीफे को भी इस घटनाक्रम से उपजी प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। जिसके निरितार्थ चुनाव के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया के प्रति असंतोष के रूप में देखे गये। बहरहाल, अदालत के फैसले के बाद उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन्होंने सारे प्रकरण के प्रति आंखें मुद्रे रखी। आखिर क्यों हमारे राजनीतिक दल भी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता कायम नहीं रख पाते? क्यों हर मामले में कोर्ट को दखल देकर न्यायसंगत चुनाव का मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है? यदि कोर्ट नगर निगम और पालिकाओं के छोटे मामलों में बार-बार हस्तक्षेप करने को बाध्य होगी तो क्या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सुलझाने के लिये अदालत का समय प्रभावित नहीं होगा? कहीं न कहीं अदालतों में लगे वादों के अंतर्वार के मूल में यह वजह भी है कि राजनीतिक दलों के पचड़े सुलझाने में कोर्ट का समय अनावश्यक रूप से व्यव होता है। माना जाना चाहिए कि चंडीगढ़ महापौर के मामले में दिया गया शीर्ष अदालत का फैसला भ्रष्ट राजनेताओं के लिये सबक ही नहीं, मार्गदर्शक नजीर भी साबित होगा। बहरहाल, शीर्ष अदालत के फैसले ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राणवायु दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप सुप्रीमो ने पुरानी कहावत दोहराते हुए कहा भी कि 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं'। अब वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा पर नये सिरे से हमलावर हो रहे हैं। बल्कि वे भाजपा के आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के दावों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अबअसल, चंडीगढ़ मेरय पद पर आप व कांग्रेस के साझे प्रत्याशी की जीत को अब ईंडिया गठबंधन की जीत के रूप में दर्शाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले महापौर चुनाव में ऊंच-नीच हुई थी, लेकिन मामला इतनी चर्चा में नहीं आया। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव को लेकर आप व कांग्रेस के लिए जीते जाएंगे जो नहीं देखते हैं।

# विगड़ती क बंगाल की

## चर्चित गणनीय

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र  
दी २०६ श्री विष्णुप्रसाद योगीपाल लाल

## १-२०६, सा, विमूर्तखण्ड

अपने साधारण व्यवसायिक वर्गीकरण विज्ञापन को क्लासीफाइड द्वितीये में अकर्षक दिनांक के साथ प्रकाशित करता है।

उत्पल न आकपक डिजाइन क साथ प्रकाशित करवाए  
 अधिकतम साइज 25 सेमी x 3 सेमी

न्यूनतम साइज 4 सेमी x 3 सेमी

दर- रु . 70/- प्रति स्वर्वाँयर सेमी

कलासीफाइडस विज्ञापन पर विशेष ऑफर  
 स्कीम  $2+1$ ,  $3+2$ ,  $5+5$ ,  $10+12$ ,  $12+20$   
 00 रु. 25 शब्दों तक, ऑफर 8 रु. प्रति शब्द अतिरिक्त 50 शब्द  
 अधिकतम, वर्गीकरण डिस्प्ले 70 रु. प्रति स्वर्वाँयर सेमी

गर्भ-विज्ञापन सर्वेक्षण नाना भुगतान पर एक साथ ब्रूक कराना अनिवार्य है। विज्ञापन सम्बन्धित कॉलम में ही प्रकाशित होंगे।

**क्लासीफाइड सब बुकिंग से संबंधित जानकारी हेतु सम्पर्क करें:-  
फोन नं-0522-4075237**

# रोजगार सूजन पर मोदी सरकार की चुप्पी पर उठते सवाल

ନନ୍ଦ କନ୍ରୀ

यह समझना मुश्किल है कि सरकार रोजगार सूजन पर चुप क्यों है जबकि वह साल-दर-साल बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च का लगातार दावा कर रही है। नयी नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर सालगातार कम हो रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोजगारी का लगातार बढ़ना चिंता का कारण बनता जा रहा है। वर्तमान में, देश का वार्षिक सकल धरेलू उत्पाद विस्तार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हुए यह रोजगारहीन आर्थिक विकास की तरह दिखता है, जबकि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ा होता है। सरकार ने देश के सतत विकास के लिए, 2019 से 2023 तक पांच साल की अवधि में बुनियादी ढांचे पर 14 खरब डॉलर खर्च करने की अपनी योजना के बारे में अक्सर बात की थी। इस तरह के बुनियादी ढांचे के खर्च से देश में स्वचालित रूप से लाखों नौकरियां पैदा होनी चाहिए थीं। यदि हाँ, तो सरकार बुनियादी ढांचे के खर्च से जुड़े रोजगार सूजन पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने वार्षिक बजट में रोजगार सूजन के आंकड़ों को क्यों छोड़ दिया? आर्थिक मामलों के विभाग के तहत वित्त मंत्रालय की बुनियादी ढांचा नीति और योजना प्रभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, राजमार्ग और एक्सप्रेस वे के साथ-साथ सरकार के समग्र बुनियादी ढांचे के खर्च में सीधे शामिल हैं। रोजगार सूजन पर मंत्रालय की लंबी चुप्पी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, भारत के 2030 तक सात वित्तीय वर्षों में बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की संभावना है, जो 2017 और 2023 के बीच पिछले सात वित्तीय वर्षों में खर्च किए गए 67 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है। हालांकि, इन्प्रास्ट्रक्चर फंड आवंटन और परियोजनाओं के समय पर नियादिन के बीच बहुत अंतर



है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तथाकथित बजट आवंटन और उनके कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी में कुछ गंभीर गड़बड़ी है। राष्ट्रीय बजट शायद ही परियोजना कार्यान्वयन में अत्यधिक देरी के बारे में बात करता है, जिसके कारण कई प्रमुख परियोजनाएं रद्द हो गईं और अन्य की लागत में भारी वृद्धि हुई। अधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले जुलाई माह तक लगभग 809 विलंबित परियोजनाओं की लागत में 4.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई। सेंटर फॉर्मॉनिटरिंग इंडिया इकानोमी (सीएमआई) की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 117 अरब डॉलर (7.63 लाख करोड़ रुपये) की परियोजनाएं वित वर्ष 2018 में खत्म कर दी गईं यह संदिग्ध है कि क्या बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर वार्षिक बजट आवंटन वास्तविक परियोजना खर्च या गैर-खर्च की सही तस्वीर प्रदान करता भी है? रोजगार सूजन के पहलू पर सरकार की लगातार चुप्पी के पीछे यह एक कारण हो सकता है। इन परिस्थितियों में, जौदार बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन प्रस्ताव कुछ हद तक खोखले लगा सकते हैं। 2023-24 के आखिरी पूर्ण बजट में बुनियादी ढांचे के लिए सरकार का पूंजी निवेश परिव्यय 33प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये (122 अरब डॉलर) कर दिया गया था। सरकार का रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर 2.40 लाख करोड़ रुपये

(29बिलियन) खर्च करने का इरादा है, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय और 2013-14 के आवंटन का लगभग नौ गुना होने का दावा किया गया है। अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए लगभग 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 75,000 करोड़ रुपये (9बिलियन) के निवेश के साथ प्राथमिकता पर लेने के लिए पहचाना गया था, जिसमें निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये (1.8बिलियन डॉलर) भी शामिल थे। इनका उद्देश्य बंदरगाह, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 50 और हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग मैदानों को पुनर्जीवित करके क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करने की योजना बनाई है। उमीद तो यह थी कि सरकार 2024-25 के बोट-ऑन-अकाउंट (लेखानुदान) बजट में आम आदमी और विशेष रूप से करदाताओं को जानकारी देगी तथा रोजगार पर उनके प्रभाव के बारे में परियोजनाओं के कार्यन्वयन की स्थिति पर एक पूरी रिपोर्ट प्रदान करेगी। दुर्भाग्य से, पूँजी निवेश के उन बड़े-बड़े अनुमानों से परे बढ़ती बेरोजगारी की गंभीर हकीकत भी छिपी है। सरकार यह बताने में असमर्थ है कि इतने बड़े निवेश पर्यास नौकरियाँ पैदा करने में क्यों विफल हो रहे हैं। हर महीने नौकरी की तलाश कर रहे युवा पुरुषों और महिलाओं की बढ़ती संख्या से स्थिति और खराब होती जा रही है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगारी दर लगभग आठ प्रतिशत के आसपास मंडरा रही है, जो लगभग पांच साल पहले लगभग पांच प्रतिशत थी। बताया गया है कि रोजगार के लिए कानूनी उम्र के 900 मिलियन भारतीयों में से श्रम बल भागीदारी दर छह साल पहले 46 प्रतिशत से गिरकर 40 प्रतिशत हो गई है। विश्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2010 और 2020 के बीच, भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या 26 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत हो गई। सीएमआई के एक अनुमान में कहा गया है कि 2022 तक महिला श्रम बल की भागीदारी घटकर नौ प्रतिशत रह गई थी। श्रम बाजार संकट के दौर से गुजर रहा है। नई सरकारी नौकरियाँ कम हैं। मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़

रहा है। विभिन्न स्तरों पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के नेताओं सहित संगठित नौकरी दलालों द्वारा इसका शोषण किया जाता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में, कंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूरे राज्य में फैले बड़े कैश-फॉर-नौकरी रैकेट का खुलासा किया है। राज्य-स्तरीय चयन परीक्षा पास करने वाले हजारों सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार महीनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कथित भर्ती घोटाले के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। पश्चिम बंगाल, देश के कई क्षेत्रीय पार्टी शासित राज्यों में से एक, तथा नौकरी की सबसे अधिक कमी वाले राज्यों में से एक है। बिहार, ओडिशा, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग अन्य नौकरी-भूखे राज्यों में से हैं। बेटरप्लेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक अर्थिक चुनौतियों और अनिश्चित आर्थिक माहौल के कारण 2022-23 में भारत में प्रंत्लाइन नौकरियों की संख्या में 17.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। बेटरप्लेस एशिया का सबसे बड़ा मानव पूँजी एसएएस समाधान है जो उद्यमों को अपने फ्रंटलाइन श्रमिकों के संपूर्ण जीवनचक्र का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। जाहिर है, भारत में मौजूदा रोजेजगारी की स्थिति का सरकार के बुनियादी ढांचे के निवेश के दावों से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि पूरी दुनिया में देखा गया है, बुनियादी ढांचा निवेश रोजगार सृजन के लिए एक इंजन की तरह काम करता है। आर्थिक विकास की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश और नौकरी में वृद्धि के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और जीवन की बेहतर गुणवत्ता बुनियादी ढांचे के विकास के बुछ प्रमुख लाभ हैं। सरकार का बड़ा बुनियादी ढांचा निवेश देश के आम नागरिकों के रोजगार सृजन और जीवन की गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन से मेल खाने में विफल रहता है। यह संभव है कि वास्तविक जमीनी निवेश बजटीय निधि आवंटन से कापी कम हो। इससे शायद यह समझा जा सकता है कि सरकार रोजगार सृजन पर चुप क्यों है।

# क्या हम आजाद हैं?

सर्वमित्रा सुरजन

1989 में एक फिल्म आई थी मैं आजाद हूँ। जब यह फिल्म आई थी, तब भारत को आजादी मिले 40 साल हो चुके थे। इन चार दशकों में देश ने कई उत्तर-चढ़ाव, गम और खुशी के पल देखे। इन सबके बीच लोकतंत्र और सविधान के संरक्षण का भाव पत्ता-फूलता रहा। उस दौर में समाज में एक बड़ी चिंता भ्रष्टाचार को मिटाने की थी और कई फिल्मों में इसे देश के लिए सबसे बड़ी चुराई के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था, जिसके खाते के लिए नायक आगे आता है। तब तक न राम मंदिर के आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकाली गई थी, न आम लोगों को इस बात का एहसास था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का अपराध भी किया जा सकता है। उदारीकरण भी देश में तब तक नहीं आया था, इसलिए समाज के उच्च वर्गों की जिंदगियों और सरोकारों से मध्यमवर्गीय लोगों के सरोकार बहुत अलग थे। इसलिए तब इस फिल्म में जिस तरह सियासत, मीडिया और कारोबार जगत का गठजोड़ दिखाकर भ्रष्टाचार का नया रूप दिखाया गया, जिस अंदाज में आम आदमी के सवालों को उठाया गया, वो वास्तविकता से दूर होने लगे थे। फिल्म में मीडिया मालिक कहता है कि झूट जोर से बोला जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। वह झूट के कारोबार से पहले मुख्यमंत्री और फिर दिल्ली की सत्ता पर बैठने की महत्वाकांक्षा पालता है, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देना चाहता है। उसकी निगाह में लोकतंत्र का कोई मोल नहीं है। आज से 35 साल पहले इस तरह की कहानी काफ़ी हृद तक नाटकीय लगी थी, क्योंकि लोकतंत्रिक समाज तो इस खुशफहमी को पाले हुए था कि हिटलरी सोच हिटलर की मौत की साथ ही खत्म हो चुकी है। देश तो यही मानकर चलता था कि अनेकता में एकता वाले भारत में नफरत कभी भी टिक नहीं सकेगी, भारत की हस्ती कभी मिट नहीं सकेगी। लेकिन आज 2024 के भारत को देखें तो लगता है कि जो कुछ 1989 में दिखाया गया, वह एक तरह से देश

का भावा तस्वर हा था। पछले 15 दिनों का कुछ घटनाओं को देखें। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में पीठासी अधिकारी ने ही मतपत्रों में अपनी ओर से क्रॉस के निशान लगाकर आप और कांग्रेस के गठबंधन को हराया और भाजपा को जिता दिया। चूंकि सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया और आप ने इस मामले के अदालत में ले जाने की हिम्मत दिखाई, इस बजह से सच्चाई सामने आई। अब आप के कुलदीप कुमार के सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का मेयर बनाया है और पीठासी अधिकारी अनिल मसीह पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना हो रही है लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदालत को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई यह प्रकरण खुश होने का है। क्या इस घटना को अंत भला तो सब भला कहकर भुलाया जा सकता है, या पिर इसे लोकतंत्र के लिए एक गहरी चुनौती मानते हुए हमेशा याद रखा जाना चाहिए? अदालत ने अनिल मसीह पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन मसीह ने क्या अपने लिए बोटों से छेड़छाड़ की थी, या पिर किसी और के फयदे के लिए। वो कौन सी ताकें हैं, जिन्होंने दूर्योगी पर तैनात एक अधिकारी से असंवेधानिक काम करवाए, क्या कभी उनकी शिनाख हो पाएगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान बोटों की गिनती के आदेश दिए। क्या इसे सामान्य बात माना जा सकता है। क्योंकि चुनाव करवाने और बोट गिनवाने का काम तो चुनाव आयोग का है। अगर अदालतों में अब चुनाव के फैसले, बोटों की गिनती होने लगे, तो सोचिए कि लोकतंत्र किस बदहाली का शिकार हो चुका है। 30-32 बोट तो अदालत में गिन लिए गए मगर लोकसभा चुनावों में 97 करोड़ मतदाताओं के बोट तो अदालत में नहीं गिने जा सकते, तो क्या निर्वाचन आयोग इस बात की गारंटी लेगा कि 97 करोड़ बोटों में कोई हेरफेर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट तक चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला पहुंचा तो इंसाफहो गया, लेकिन क्या देश में होने वाली हर नई सापेक्ष अदालत की चौखट तक पहुंच पाएगी और क्या हर बार अदालत से इंसाफमिल पाएगा। अभी किसान पिर से दिल्ली की सीमा पार करने

क लए निकल पड़ ह आर एक बार अपर उन पर पजाब-हरियाणा की शंभू सीमा पर आंसू गैस के गोले दागे गए। जब कांवड़ लेकर बेरोजगार नौजवानों की भीड़ सड़कों पर आती है और तब कानून व्यवस्था से लेकर दैनंदिन जीवन प्रभावित होता है, तब तो सरकार हेलीकाप्टर से उन पर पूल बरसाती है। मानो युवाओं के कांवड़ ढोने से देश की तरकी हो रही हो, समृद्धि आ रही हो। लेकिन जिन किसानों की कड़ी मेहनत से देश का पेट भरता है, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता आती है, उनके साथ दुश्मनों की तरह सलूक किया जा रहा है। किसान अपनी मेहनत का सही दम ही मांग रहे हैं, मगर सरकार उनसे सौदेबाजी वाले अंदाज में बात कर रही है कि 23 नवंबर हम केवल 5 फसलों पर एमएसपी देंगे, वो भी 5 साल के कॉटैक्ट पर। इसके बावजूद किसान शांति के साथ ही आगे बढ़ने का प्रस्ताव रख रहे हैं और सरकार उन पर आंसू गैस के गोले गिराने के साथ दावा कर रही है कि किसान उसकी प्राथमिकता में हैं और वो बातचीत से समाधान निकालना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफहोती तो समाधान पहली बारा में ही निकल जाता, उसके लिए चार बार बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है मानो मैं आजाद हूं का खलनायक किरदार पर्दे से बाहर निकल कर जीवंत हो चुका है। जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देना चाहता है। कभी छात्रों को कुचला जाता है, कभी किसानों को, कभी अग्निवीर के जवानों को। विपक्ष को सीधे-सीधे कुचलने की जगह उनमें पूर्ण डलावाकर सत्ता की राह बनाई जा रही है। इस राह में नफरत, हिंसा और अराजकता सबका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान में गांधी की धोती-चादर, और नेहरू की शेरवानी-गुलाब को देखकर पहचान का चलन था, लेकिन अब जातीदार टोपी, पगड़ी और बुरके से पहचान का विनाशकारी मंत्र भक्तों को दिया गया। इस मंत्र के ताजा शिकार बने आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह, जो प.बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली में अपने दल-बल के साथ ड्यूटी पर थे। संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में विवाद चल रहा है और

आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश जब जसप्रीत सिंह ने की, तो उन्हें खालिस्तानी कहा गया। जसप्रीत सिंह का आरोप है कि उन्हें भाजपा के लोगों ने खालिस्तानी कहा, क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी। सोशल मीडिया पर इस दौरान हुई झटके का वीडियो वायरल है, जिसमें जसप्रीत सिंह कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर उन पर टिप्पणी नहीं की जाए। अब तक मुसलमानों को उनके पहनावे और खाना-पान के लिए निशाने पर लिया जा रहा था, बार-बार उनसे देशभक्तिसाक्षित करने कहा जाता है। ईसाइयों के खिलाफ भी ऐसा ही माहौल बनाया जा चुका है। मिशनरी स्कूलों में हिंदुत्व को खतरा है, इसकी झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं। और अब नफरत का विस्तार सिख कौम तक होता दिख रहा है। जसप्रीत सिंह अपने लिए जबाब देने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसे कितने पगड़ीधारी हैं, जो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, तो क्या सरकार यह गारंटी दे पाएगी कि वह सबकी रक्षा करेगी। अगर सरकार ऐसी गारंटी नहीं दे सकती, तो पिछ सत्तारूढ़ दल क्या पिछ सत्ता पर कविंज होने का अधिकारी है, यह लोगों को सोचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में आने का दावा तो कर ही चुके हैं, अभी उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें विदेशों से आमंत्रण भी मिलने लगे हैं, क्योंकि वे भी भाजपा की जीत को लेकर आश्रस्त हैं। ये सीधे लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाला बयान है, क्योंकि इसमें मोदी सफातौर पर कह रहे हैं कि उन्हें ही नहीं दूसरे देशों के राष्ट्रध्यक्षों तक को चुनाव से पहले नतीजों का पता है। क्या ये भारत की आंतरिक नीति में दखलानी नहीं है। अबकी बार ट्रूप सरकार बोलकर नरेन्द्र मोदी ने जो गलती की थी, यह उसी का दोहराव है। एक ही गलती बार-बार हो तो वो गलती नहीं आदत कहलाती है। क्या लोकतंत्र की उपेक्षा की आदत हम आजादी के अमृतकाल में देख रखे हैं मैं आजाद हूं से लेकर क्या हम उस दौर में आ पहुंचे हैं, जहां हमें पूछना पड़े कि क्या हम आजाद हैं। या पिछ नफरत, स्वार्थ और हिंसा की भूषि राजनीति के हम गुलाम बन चुके हैं।

# बिंगड़ती कानून व्यवस्था का खामियाजा पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है

किसी भी देश में आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए उस देश में सामाजिक शार्ति बनाए रखना अति आवश्यक है। यही शर्त किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति के सम्बंध में भी लागू होती है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहे राज्यों के बीच अग्रिम पर्किं में रहता आया है। परंतु, हाल ही के वर्षों में पश्चिम बंगाल में शार्ति भंग होती दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव स्पष्टतरू इस राज्य के आर्थिक विकास पर भी विपरीत रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक ताना बाना छिन भिन्न होता दिखाई दे रहा है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बन गया है, विशेष रूप से सनातन संस्कृति का पालन करने वाले बंगाल के शार्ति प्रिय नागरिकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही के समय में पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों जैसे संदेशखाली इलाके में महिलाओं पर अत्याचार आम बात हो गई है। संदेशखाली, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिलों का एक छोटा कस्बा है। यह बांग्लादेश की सीमा से सटी सीमावर्ती क्षेत्र भी है, जहां हिंदू अनुचित जातियों की आबादी बहुलता में है। संदेशखाली, पश्चिम बंगाल की उन 14 विधानसभा की सीटों में शामिल हैं जोकि भारत बांग्लादेश सीमा से सटी हुई हैं। दुर्भाग्य से संदेशखाली सहित यह सभी विधानसभा सीटें अतिवादी संगठनों द्वारा समर्थित सुनियोजित घटियंत्र का एक हिस्सा बन गई हैं। इन 14 सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्रों में संदेशखाली से अन्य सात सीटें द्वारा सुनियोजित घटियंत्र का हिस्सा बन गई हैं।

है। यहां की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश का घट्टयंत्र भी उच्च स्तर पर हो रहा है। वास्तव में, यह क्षेत्र पाकिस्तानी खुपिमा एजेन्सी पैप की आतंकी गतिविधियों के अलावा तमाम आपराधिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। कुछ समय पहले तक संदेशखाली में मुस्लिम जनसंख्या नहीं के बराबर थी लेकिन अवैध घुसपैठ के चलते यहां असामाजिक तत्वों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह इलाका जनसांख्यिक परिवर्तन की चपेट में आ गया है। इसमें सबसे बड़ी आबादी अब रोहिग्याई मुसलमानों की हो गई है। गांव करने वाली बात है कि विगत चुनावों के दौरान घटिट सभी आपराधिक घटनाओं में अधिकतर अपराधी असामाजिक तत्व मुस्लमान ही पाए गए थे। यह मामले गौ-तस्करी से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े रहे हैं। इस तरह के सभी गैरकानूनी मामलों में मुस्लिम ही अभियुक्त पाप जाते हैं। संदेशखाली में जो कुछ सामने आया है अथवाएँ आ रहा है, यह कोई पहली बार घटिट हुई वारदातें नहीं है। हिंदू महिलाओं के साथ गैंग रेप की एक नहीं बल्कि सैकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जब भी आवाज उठायी है तो परिणाम में उन्हें ही निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। न सिर्फ संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है बल्कि उनके घरों को भी जला दिया गया है। इस क्षेत्र में हिंदू अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों को इस इलाके के दबंग समैलियां आरंभ कर दिया जाता है जो लोगों से

जबरन उठा ले जाते हैं। इस क्षेत्र में तस्करी, मादक पदार्थ, हथियार, गोमांस आदि अपराधों में सलिस शेख शहंशाह जैसे मुस्लिम दबंगों का बोलबाला है। हाल ही में शेख शहंशाह के ठिकानों पर छापेमारी के लिए गई प्रवर्तन निदेशालय (म्व) की टीम पर उसके गुर्गों द्वारा हिंसक हमला भी किया गया था। इस हमले में म्व के कई अधिकारी गम्भीर रूप से घायल हुए थे। इस इलाके में नौकरीध्रोजगार, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने की आड़ में भी अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। पश्चिम बंगाल के विशेष इलाके सदेशखाली में घटित उक्त घटनाओं का वर्णन केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। वरना, पूरे पश्चिम बंगाल में ही आज अराजकता का माहौल है जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगति को विपरीत रूप में प्रभावित कर रहा है। लगभग 1960 के दशक तक पश्चिमी बंगाल की औसत प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल, भारत के प्रथम तीन सबसे अधिक धनी राज्यों में शामिल था। पहले दो राज्य थे—महाराष्ट्र एवं गुजरात। 1980 का दशक आते आते पश्चिम बंगाल की औसत प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय के लगभग बराबर तक नीचे आ गई थी। 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ने लगी और पश्चिम बंगाल का स्थान देश में 7वें स्थान पर आ गया। वर्ष 2000 में और भी नीचे गिरकर 10वें स्थान पर आ गया एवं वर्ष 2011 में यह 11वें स्थान पर आ गया।

औसत प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 14वें स्थान पर आ गया है। इसी प्रकार, वर्ष 1993-94 एवं 1999-2000 के बीच पश्चिम बंगाल में औसत प्रति व्यक्ति आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की गई थी जबकि भारत का राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 4.6 प्रतिशत था। अगली दशाब्दी में पश्चिम बंगाल में औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर गिरकर 4.9 प्रतिशत रह गई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2019-20 के दौरान पश्चिम बंगाल में औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर और भी नीचे गिरकर 4.2 प्रतिशत हो गई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 5.2 प्रतिशत रहा। इस प्रकार पश्चिम बंगाल एवं राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में यह अंतर और भी बढ़ता ही जा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल में विकास दर राष्ट्रीय स्तर पर औसत विकास दर से अधिक थी। परंतु, वामपंथी दलों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम हो गई थी। पश्चिम बंगाल पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा है। विशेष रूप से वामपंथी दलों एवं तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित होती रही है। वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति सकल धरेलू उत्पाद 157,254 रुपए था जबकि विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सकल धरेलू उत्पाद का अनुमान 2,111 रुपये ही है।





फिल्म फे स्टिवल अवॉर्ड्स में नयनतारा  
के साथ चलेया गाने पर झूमे शाहरुख खान



बॉलीवुड मेगास्टर शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में काम करने वाली साड़थ एकट्रेस नयनतारा एक पुरस्कार समारोह में किंग खान के साथ नजर आईं, जहां उन्होंने खूब मस्ती की। हाल ही में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में नयनतारा को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। कार्यक्रम के एक वीडियो में दिखाया गया है कि जब वह पुरस्कार लेने के लिए मंच पर चढ़ीं तो शाहरुख ने उन्हें सहारा दिया। शाहरुख ने नयनतारा के साथ जवान फिल्म के गाने चलेया पर हुक स्टेप भी किया। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। निर्देशक एटली की फिल्म जवान से हिंदी सिनेमा में डेव्यू करने वालीं नयनतारा ने गोल्डन येलो कलर की साड़ी पहनी थी और अपने बालों का जूँड़ा बना रखा था। उन्होंने अपने लुक को चोकर और मैचिंग इयररिंग्स के साथ पूरा किया। फिल्म फे स्टिवल अवार्ड्स में शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। मुंबई में हुए अवार्ड शो में निर्देशक एटली, उनकी पत्नी प्रिया और संगीतकार अनिकृट मित्रनंद समेत जवान की पारी टीम मौजूद थी।

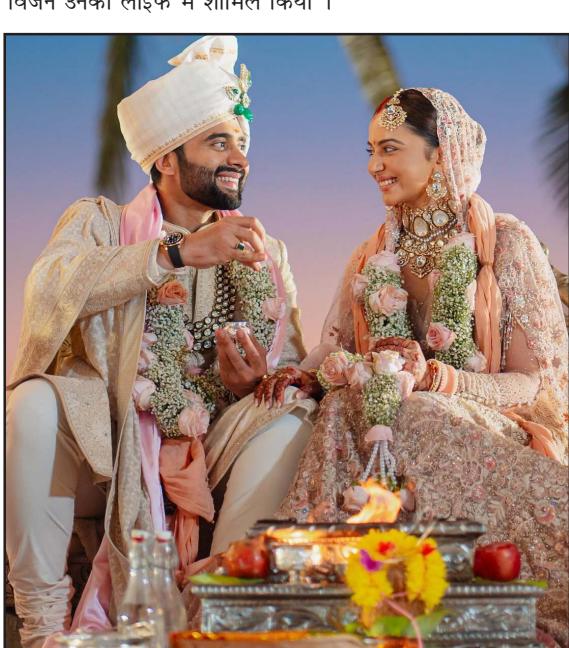
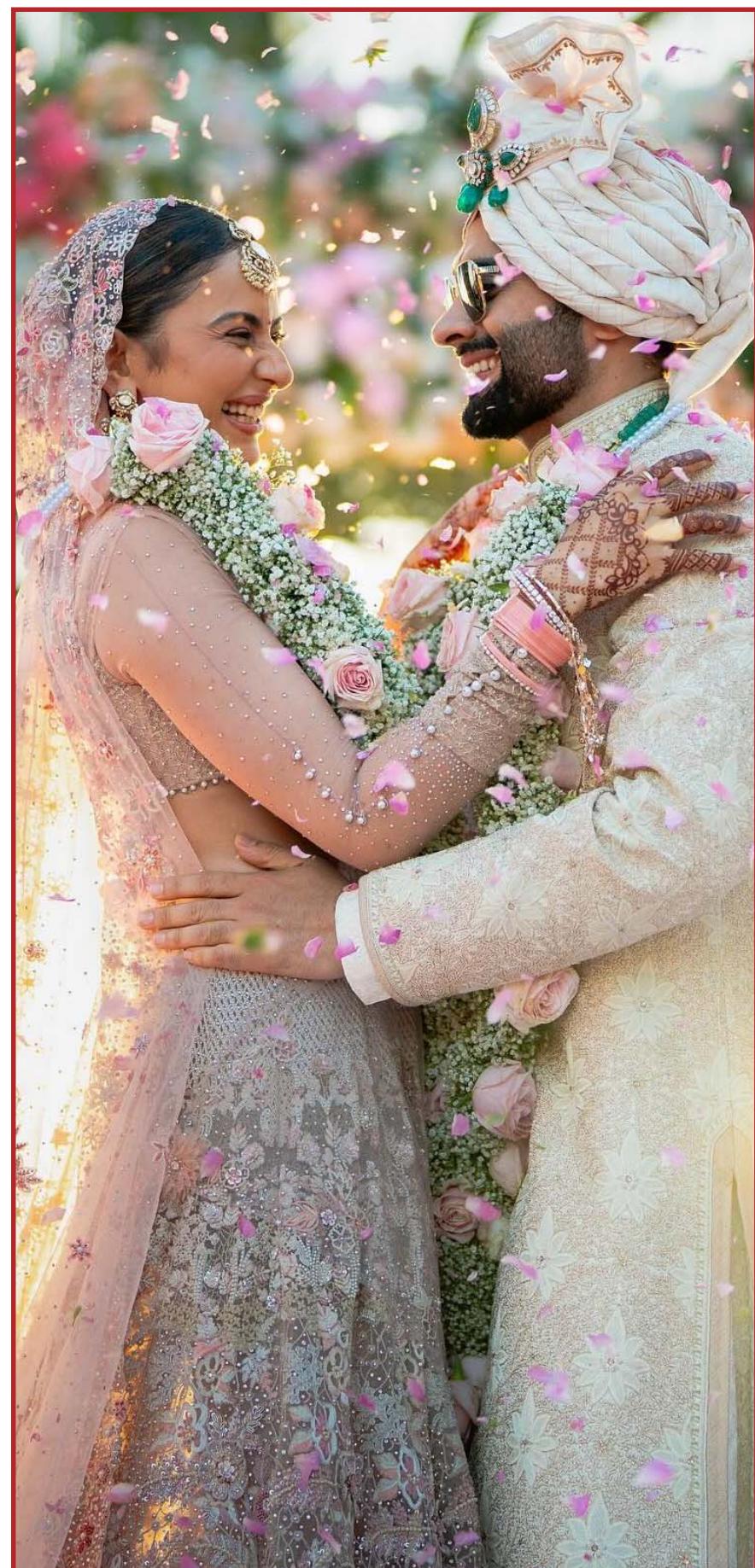
ਬੋਲੀਤੁਹਾਰ



**माँमो करोना का दिखा बांसो लुक तो बुआ साहा केजुअल  
में आई नजर, जेह की बर्थडे पार्टी में सेलेज़स का मेला**

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और बेबो करीना कपूर के लाडले बेटे जेह अली खान आज 3 साल के हो गए हैं। इस मौके पर इस रॉयल कपल ने रणधीर कपूर के घर में एक बड़ी से पार्टी का आयोजन किया। यहां पर बी-टाउन सेलेब्स अपने-अपने बच्चों के साथ पहुंचे। करीना यहां सैफ के हाथों में हाथ डाले नजर आई और बेहद खुशी से पैपराजी को कर रही थीं। लुक की बात करें तो करीना ने ब्लू जींस के साथ येलो टी-शर्ट वियर की, साथ में हरे रंग के ब्लेजर को पेयर किया था। व्हाइट स्नीकर्स और ब्लैक हैंडबैग के साथ लुक उन्होंने को पूरा किया। वहीं सैफ कुर्ते पाजामे में हैंडसम लगे।

लीवुड के नवाब सैफ अली खान और बेबो करीना कपूर के लाडले बेटे जेह अली खान आज 3 साल के हो गए हैं। इस मौके पर इस रॉयल कपल ने रणधीर कपूर के घर में एक बड़ी से पार्टी का आयोजन किया। यहां पर बी-टाउन सेलेब्स अपने-अपने बच्चों के साथ पहुंचे। करीना यहां सैफ के हाथों में हाथ डाले नजर आई और बेहद खुशी से पैपराजी को आम कर रही थीं। लुक की बात करें तो करीना ने ब्लू जींस के साथ येलो टी-शर्ट वियर की, साथ में हरे रंग के ब्लेजर को पेयर किया था। व्हाइट स्लीकर्स और ब्लैक हैंडबैग के साथ लुक उन्होंने को पूरा किया। वहीं सैफ कुर्त पाजामे में हैंडसम लगे। बर्थडे बॉय जेह अली खान ने कैजुअल जींस शर्ट कैरी की। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था, जेह बालों में लगा जेल। बड़े भैया तैमूर लगता है स्कूल से सीधा पार्टी में आए थे, वो स्कूल यूनिफॉर्म में स्पॉट हुए। मामा रणधीर कपूर अपनी बेटी राहा और भाँजी समारा के साथ पार्टी में पहुंचे। एकट्रेस सोनम कपूर ने बेटे वायु के साथ नजर आई, इस दौरान **प्रैपरदेपें** ने गोल्डन कलर की प्रिंटेड ड्रेस पहनी। नेहा धुपिया ने ब्लैकसिवतंस करतमे में नजर आई। वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ पार्टी अटेंड करने पहुंची। बुआ सोहा अली खान और कुणाल खेमू बेटी इनाया के साथ पार्टी में पहुंचे। दोनों कैजुअल लुक में थे वहीं जेह के नाना-नानी रणधीर और बबीता ने व्हाइट में ट्रिवनिंग की।



**ਵਰਣ ਧਵਨ ਸੇ ਲੇਕਰ ਨਧਨਤਾਰਾ  
ਤਫ਼, ਸੇਲੇਸ਼ ਨੇ ਦੀ ਰਫੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਹ  
ਔਰ ਜੈਕੀ ਭਗਨਾਨੀ ਕੋ ਬਧਾਈ**

कुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी 21 फरवरी को गोवा में शाही शादी के बंधन में बंध गए हैं। इसके बाद कपल ने बिना देरी करते हुए अपनी शादी की तस्वीरें भी सबके साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। अब बॉलीवुड के सेलेब्स उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक रकूल प्रीत सिंह मिसेज भगनानी बन चुकी हैं कपल ने बीते दिन गोवा में परिवार और दोस्तों के बीच शाही शादी की और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें भी शेयर की। अब सामंथा रुथ, मृणाल ठाकुर से लेकर मलाइका अरोड़ा तक कई सेलेब्स और फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। कपल ने अपनी शादी की फोटोज को सोशल मीडिया पर सबके साथ शेयर किया, जिसके बाद बॉलीवुड के सितारे उन्हें बधाई देने में लग गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, ‘आप लोगों को बधाई’। सोनल चौहान ने लिखा, ‘आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई’। भूमि पेडनेकर ने रकूल प्रीत के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘सबसे खूबसूरत 3 दिन’। इनके अलावा दीया मिर्जा ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘बधाई, हमारा सारा प्यार और आशीर्वाद’। राशि खन्ना ने शादी की बधाई देते हुए कमेंट में लिखा, ‘आप लोगों को बधाई!!!!’. जेनेलिया देशमुख ने भी दोनों को शादी की बधाई देते हुए लिखा, ‘आप लोगों को बधाई’, रितेश देशमुख ने भी कमेंट करते हुए लिखा, ‘बहुत बहुत बधाई हो आप खूबसूरत लोगों को’। मृणाल ठाकुर ने भी दोनों को बधाई देते हुए लिखा, ‘बधाई हो’ और भी कई सितारे कमेंट्स में बधाई दे रहे हैं। एक नहीं बल्कि दो रिटायर-रिवाजों से शादी की है बता दें कि रकूल प्रीत सिंह सीख परिवार से है और जैकी भगनानी सिंधी परिवार से आते हैं, पहली पंजाबी और दूसरी सिंधी रिवाज से शादी किया। रकूल प्रीत सिंह ने अपनी शादी में डिजाइनर तरुण तहिलियानी का पेस्टल लहंगा पहना था। इस लहंगे में थ्रेड और पर्ल से हैंडवर्क किया गया था। डिजाइनर तरुण तहिलियानी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर लहंगे की जानकारी शेयर कर दी है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैशन में लिखा, ‘शाम की शादी के लिए रकूल ने एक कॉन्टेप्टरेरी लेनिकन वाइंड्रेट परसोना को इमैजिन किया। तरुण तहिलियानी ने एक

## »» बॉलीवुड ««

कहते हैं ना जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। 12वीं फे ल में पास होने वाले एक्टर विक्रांत मैसी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। एक फिल्म से लाखों दिलों में खास जगह बना चुके एक्टर अपने एक पुराने ट्वीट को लेकर विवाद में फंस गए हैं। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें सामने आकर खुद माफी मांगनी पड़ी फिल्म 12वीं फे ल, 2023 की सबसे चर्चित रिलीज में से एक रही और इस हिंसायरिंग स्टोरी वाली फिल्म को दर्शकों ने भी खूब सराहा। सच्ची कहानी पर आधारित 12वीं फे ल उन लाखों छात्रों के संघर्ष पर आधारित है जो यूपीएससी प्रवेश परीक्षा देते हैं। इस फिल्म में विक्रांत का दमदार काम देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक पुराना ट्वीट बायरल हो गया। दरअसल ये ट्वीट 2018 का है जब जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस पर एक्टर ने गुस्सा जाहिर करते हुए एक कार्टून शेयर किया था। इस कार्टून में हाथ में अखबार थामे देवी सीता कार्टून में भगवान राम के बारे में बताती नजर आई। इस पोस्ट के कैशन में लिखा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा अपहरण रावण ने किया था, आपके भक्तों ने नहीं। इस कार्टून को देख लोग काफी भड़क गए हैं। ऐसे में एक्टर ने अपनी गलती मांगते हुए लिखा-2018 में मेरे एक ट्वीट के संदर्भ में, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा रुहिंदू समुदाय को चोट पहुंचाने, बदनाम करने या अपमान करने का मेरा इरादा कभी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं मजाक में किए गए एक ट्वीट के बारे में सोचता हूं, तो समझ आता है कि यही बात एक अखबार में छपे कार्टून को जोड़ लिया भी कही जा सकती थी। और मैं अन्यान्य विनायक के साथ उस मध्ये ल्योगें से मापी मांगना जाता हूं, किंतु देम पार्दीनी हूं।



# दोस्तों के साथ भारत की इन खास जगहों का करें दूर

## एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाएं

अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की सबसे बेस्ट प्लेसेस है। एवं से लेकर दक्षिण तक इन जगहों पर दूर कर सकते हैं। इस आर्टिकल में बताएंगे भारत की शानदार जगहें जिन्हें आप अपने घूमने का डेरिटेशन बना सकते हैं। तो बिना देर किए इन टॉप जगहों के बारे में बताते हैं। इस टॉप जगहों के बारे में बताते हैं। आप भी महीने में गर्मी कम होती है ऐसे में लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। इस टॉप जगहों के बारे में बताते हैं। वह अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहाँ घूमने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान कई बच्चों के एजाम खत्म हो जाते हैं। वह अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहाँ घूमने में न ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी होती है। यह मौसम घूमने का सबसे बेस्ट होता है। पर्टनर के साथ घूमने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। वहीं, इस समय पूर्व से लेकर दक्षिण तक मौसम काफ़ी कूल होता है। बार्च में दोस्तों के साथ घूमने का अलग ही मज़ा होता है। जब कहाँ घूमने का प्लान बनाते हैं, तो ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहाँ मस्ती कर सके हैं। तो देर किस बात कि इस आर्टिकल में पहांडी का नजारा, झील, झारे, हम बताएंगे भारत की शानदार जगहें जिन्हें आप अपने घूमने का

अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की सबसे बेस्ट प्लेसेस है। पूर्व से लेकर दक्षिण तक इन जगहों पर दूर कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम बताएंगे भारत की शानदार जगहें जिन्हें आप अपने घूमने का डेरिटेशन बना सकते हैं। तो बिना देर किए इन टॉप जगहों के बारे में बताते हैं। ऐसे में लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान कई बच्चों के एजाम खत्म हो जाते हैं। वह अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहाँ घूमने में न ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी होती है। यह मौसम घूमने का सबसे बेस्ट होता है। पर्टनर के साथ घूमने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है।

डेरिटेशन बना सकते हैं।

ब्रह्मिकण

योग नगरी के नाम से फेमस ब्रह्मिकण रापिंग और ट्रेकिंग का बेहतरीन मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ पर जाना हर किसी का ड्रीम होता है।

गोवा

गोवा भारत की ऐसी जगह हजार में लोग ब्रह्मिकण के एकार्थक लुफ उठा सकते हैं।



को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

जैसलमेर

जैसलमेर राजस्थान का प्रमुख शहर में से एक है, यहाँ एक लोकप्रिय पर्यटन भी स्थल है। थार रेस्टोरन की बजह से इसे गोड़न शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा शहर है, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ यदगार वैकेंस मना सकते हैं।

मस्ती और धमाल के लिए गोवा में सुहारे समुद्र तटों के लिए पूरे विषय पर में फैसले हैं। इसके साथ ही एक लोकप्रिय नाइटलाइफ के बीच आप दोस्तों के साथ यदगार वैकेंस मना सकते हैं।

हम्पी

अगर आप दक्षिण भारत का टूर करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ मार्च के महीने में हम्पी घूमने

## धूंधली दिखती हैं, चीजें कम हो गई आंखों की रोशनी तो खाएं ये चीजें



आंखें शरीर का सबसे जरुरी हिस्सा मानी जाती हैं। परंतु आजकल के खबाब लाइफस्टाइल और गलत-ज्यानन का असर इन पर भी हो रहा है। छंटों तक लैपटॉप पर समय बिताने के कारण आंखें कमज़ोर हो रही हैं। छंटी ऊपर में बच्चों की चशमा लग रहा है। ऐसे में आंखों की ध्यान रखने के लिए अच्छी डाइट का उचाव रखना चाही रही है। आंखों की देखभाल करने के साथ-साथ आप डाइट में हल्दी चीजें शामिल कर सकते हैं। आज आपको इस आर्टिकल के बारे में बहुत कहु चूक दें। लगातार कुछ दिनों तक अंजीर का सेवन करने से आपको खुद ही पर्फेक्ट दिखने लगेगा।

**अंजीर को करें डाइट में शामिल**

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए डाइट में विटामिन-ए, सी और ई, जिंक, ल्यूटिन और जैक्सीनिथ जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर जींजों को शामिल करना जरुरी माना जाता है। वहीं अंजीर

में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पीटीयम, आयरन, कॉपर, मैंगनेश और माइक्रो-न्यूट्रियंस, फाइबर और प्रोटीन जैसे गुण मौजूद होते हैं जो आंखों के अलावा पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

**कैसे करें अंजीर का सेवन?**

आंखों की रोशनी तेज करने के लिए आप अंजीर को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं।

3-4 अंजीर को राश्वर डाइट का नींबू के फिगोकर रखें।

**मुँह की लार**  
मुख के समय उठाकर बिना कुछ किए हुए अपनी मुँह की लार को आंखों में काजल की तरह लाएं। 6 महीने तक इस तुरंत उत्तर के लिए गोवा में आई और ट्रीटमेंट खबर ढूँमें है जिसे लेते ही तुरंत चेहरे पर ग्लूमो आ जाता है। इसका इतना क्रेंज है कि जाह्वी से लेकर सोनारिका भद्रायरिया तक ये ट्रीटमेंट ले रही हैं। जब आप भी उसे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैसले खाल रखती हैं और अपने लोकर के लिए इन स्टार्ट दीवानी को बहुत अलावा भी ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेती हैं जो इनके चेहरे पर चमक बनाए रखते हैं। आजकल खबरसूर विदेशों के लिए इन स्टार्ट दीवानी में आई और लड़ियाँ खड़ी होती हैं जिसे लेते ही तुरंत चेहरे पर ग्लूमो आ जाता है।

**क्या है आईवी ट्रीटमेंट?**

इस ट्रीटमेंट को इंट्रावेनस (आईवी) विटामिन थेरेपी कहा जाता है।

इस ट्रीटमेंट को कैसे करें?

इस ट्रीटमेंट को क